



Neutral Citation No - 2026:AHC:15951

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19532/2025

यासिर अराफत

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सीमांत सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सीमांत सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें प्रार्थना खंड को सही करने की अनुमति है।
3. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि निलंबन की अवधि के दौरान, यानी 24.03.2001 से 11.03.2002 के दौरान ग्रेच्युटी को रोकने और भुगतान न करने के संबंध में, हालांकि रिट याचिकाकर्ता ने 2025 की रिट-ए संख्या 7771 को प्राथमिकता दी, जिसे 28.05.2025 को निस्तारित किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को रिट याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। हालांकि रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि ब्याज के साथ निलंबन अवधि के लिए ग्रेच्युटी और उसके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। **बिंदल एगो लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1990 की रिट याचिका संख्या 640** में एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, जिसका निर्णय 10.02.2024 को दिया गया था, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि ब्याज धन की सराहना के अलावा और कुछ नहीं है, जो समय के भीतर भुगतान नहीं करते हुए विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था।

4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का फैसला प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पहली बार में किया जाना है।

5. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा ।

22 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)